

एशियाई खेलों में लोहा मनवाने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों का भिवानी में हुआ राज्यस्तरीय सम्मान

पदक कुछ क्षणों में गले में डलता है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए खिलाड़ी अपना जीवन लगा देता है : मुख्यमंत्री

ओपन सर्व ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पदक कुछ क्षणों में खिलाड़ी के गले में डलता है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए खिलाड़ी अपना जीवन लगा देता है। इन पदकों के पीछे वर्षों का अभ्यास, अनगिनत त्याग और हार के बाद फिर उठ खड़े होने का हौसला है। भिवानी की धरती पर आज गूंज रही तालियां सिर्फ पदकों के लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत वर्षों की तपस्या, त्याग और उस अटूट संकल्प के लिए भी हैं, जिसने भारत का तिरंगा एशिया के खेल मैदानों में ऊंचा किया है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी शुक्रवार को भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित एशियाई खेलों एवं पैरा एशियाई खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों के संयुक्त सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने भिवानी के विकास को गति देने के लिए 142 करोड़ रुपये की लागत की 8 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है। इनमें 133 करोड़ 66 लाख रुपये की लागत के 6 उद्घाटन तथा 8 करोड़ 46 लाख रुपये की लागत के 2 शिलान्यास शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि आज इन सितारों के बीच आकर उनका मन वर्ष से भर गया है।

उन्होंने देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान केवल खिलाड़ियों का ही नहीं, बल्कि उनके माता-पिता, गुरुजनों, प्रशिक्षकों और सहयोगी स्टाफ के त्याग एवं समर्पण का भी सम्मान है। नायब सैनी ने कहा कि एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया। इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने 32 पदकों का योगदान दिया, जिनमें 14 स्वर्ण पदक शामिल हैं। यानी भारत के हर तीन स्वर्ण पदकों में से दो हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। इसी प्रकार, पैरा एशियाई खेलों में भारत ने 114 पदक जीतकर अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हरियाणा के पैरा खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण सहित 31

विस्तार शिक्षा संस्थान नीलोखेड़ी में पीएम-किसान उत्सव दिवस का आयोजन

ओपन सर्व ब्यूरो

नीलोखेड़ी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा संस्थान, नीलोखेड़ी द्वारा कुलपति, प्रोफेसर बी. आर. काम्बोज के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन तथा डा. नरेश कौशिक, निदेशक (विस्तार शिक्षा) के दिशा निदेशन व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आदेशानुसार पीएम-किसान उत्सव दिवस का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर संस्थान के प्रशिक्षण हॉल में आयोजित विशेष सत्र के दौरान वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों सहित विस्तार अधिकारियों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरार के समारोह (भीलंडी) से आयोजित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा और सुना गया। इस दौरान सभी ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (पीएम-किसान) योजना की 24वीं किस्त जारी किए जाने के ऐतिहासिक क्षण का सीधा अवलोकन



खिलाड़ी प्रदेश का गौरव और सरताज, उनकी उपलब्धियां दूसरे युवाओं के लिए बनेंगी प्रेरणा : श्रुति चौधरी

सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि भिवानी का भीम स्टेडियम केवल खेलों का मैदान नहीं, बल्कि उनके परिवार की यादों और क्षेत्र की खेल परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। उनके पिता चौधरी सुरेंद्र सिंह ने इस स्टेडियम की आधारशिला रखी थी और वे यहां सुबह अभ्यास के लिए आया करते थे। आज इस स्टेडियम को खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और उपलब्धियों से नई पहचान दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री का भिवानी की धरती पर स्वागत करते हुए कहा कि यहां के खिलाड़ियों ने अनुशासन

और कड़ी मेहनत के दम पर ग्रामीण स्तर से उत्कृष्ट प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इन खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। चौधरी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि भीम स्टेडियम का और विस्तार किया जाए तथा यहां खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि यहां के खिलाड़ी पहले ही अपनी प्रतिभा साबित कर चुके हैं और अब वे दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत बन सकते हैं।

पदक जीते, यानी देश के लगभग 30 प्रतिशत स्वर्ण पदक हमारे पैरा खिलाड़ियों के नाम रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खेलों में हरियाणा के अनेक सितारे चमके। मुक्केबाजी में अंकुश पंचाल और परवीन हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीते। हमारी पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर लॉस एंजेलिस ओलिंपिक 2028 का टिकट पक्का किया और इन टीमों की ताकत में हरियाणा के खिलाड़ियों का बड़ा योगदान है। कुश्ती में भारत का यह प्रदर्शन वर्ष 1962 के बाद एशियाई खेलों में सबसे बेहतरीन रहा। पैरा खेलों में सुमित अंतिल और प्रणव सूरमा की सुनहरी जीत ने पूरे देश को रोमांचित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवानी की धरती पर इस समारोह का विशेष महत्व है। ‘मिनी

डॉ. सुमित्रा मिश्रा ने उपायुक्तों को सीएम विंडो की लंबित शिकायतों के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए

ओपन सर्व ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा की वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमित्रा मिश्रा ने शुक्रवार को सभी उपायुक्तों को सीएम विंडो पोर्टल पर दर्ज लंबित शिकायतों के निपटारे में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर तुरंत किया जाए। उन्होंने समय पर कार्रवाई न होने वाली ओवरड्यू शिकायतों की निगरानी करने और विस्तृत एक्शन-टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जोर दिया ताकि शिकायत निवारण में अनावश्यक देरी न हो।

डॉ. मिश्रा चंडीगढ़ स्थित वित्तीय आयुक्त राजस्व कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। इसका उद्देश्य जिला-वार प्रदर्शन का आकलन करना और

सम्पादकीय



किसान कल्याण और विकास की नई संभावनाएं

देश की अर्थव्यवस्था और विकास की मजबूत नींव कृषि तथा ग्रामीण व्यवस्था पर टिकी हुई है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना किसी भी विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। गुजरात के बनासकांठ में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के रूप में देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का हस्तांतरण इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। यह आयोजन कृषि कल्याण के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने की संभावनाओं को भी रेखांकित करता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सहायता का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं। खेती-किसानी में बीज, खाद, कृषि उपकरण और अन्य आवश्यकताओं पर होने वाले खर्च के बीच यह सहायता किसानों को कुछ आर्थिक संबल प्रदान करती है। हालांकि, यह राशि किसानों की सभी समस्याओं का समाधान नहीं है, लेकिन समय पर मिलने वाली आर्थिक मदद उनकी दैनिक जरूरतों और कृषि संबंधी खर्चों में उपयोगी साबित हो सकती है। इस योजना की वास्तविक सफलता इस बात में है कि इसका लाभ बिना किसी बाधा के प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचे।

बनासकांठ में घोषित विकास परियोजनाओं का महत्व केवल निवेश की बड़ी राशि तक सीमित नहीं है। पशुपालन, डेयरी, कृषि प्रसंस्करण, परिवहन और सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुआयामी मजबूती देने की क्षमता रखती हैं। भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर जैसी पहल पशुधन की नस्ल सुधार और आधुनिक प्रजनन तकनीकों को बढ़ावा दे सकती है। वहीं, बनास डेयरी से जुड़े बायो-सीएनजी परियोजनाएं पशुओं के गोबर के बेहतर उपयोग, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उपयोगी साबित हो सकती हैं। कृषि क्षेत्र में केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की बेहतर व्यवस्था भी जरूरी है।

कृषि अवसंरचना कोष के तहत विकसित 521 इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित करना इसी आवश्यकता से जुड़ा कदम है। इसके अतिरिक्त 12 बागवानी क्लस्टर्स की शुरुआत से उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहन मिल सकता है। यदि किसानों को आधुनिक तकनीक, उचित भंडारण, प्रसंस्करण सुविधाएं और बाजार तक सीधी पहुंच उपलब्ध होती है, तो उनकी आय बढ़ने की संभावनाएं मजबूत होंगी। विकास परियोजनाओं के अंतर्गत परिवहन और सामाजिक सुविधाओं का विस्तार भी महत्वपूर्ण है।

जीवन में अधिक प्रदूषण तो निरर्थक प्रवृत्तियों का है

कातिलाल मांडोट

व्यक्ति दो तरह से प्रवृत्त होता है सार्थक और निरर्थक। यदि व्यक्ति अपनी सारी प्रवृत्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण करे तो उसे यह समझ में आजाएगा कि उसकी प्रवृत्तियों में निरर्थक प्रवृत्तियों का जमघट भी कम नहीं है। अनावश्यक बोलना, अनावश्यक व्यर्थ कार्य करना, व्यर्थ समय खोना, अनावश्यक विषयों में सोचते रहना केवल मोरेंजन के नाम पर अनेक अनावश्यक अश्लील हंसी मजाक करना, हानि कारक और व्यक्ति की प्रयाओं परिपाटियों का पालन करना, व्यक्ति ग्रस्त होजाने जैसे दुर्व्यसनो का सेवन करना, ताश, पती और अंकों के खेल खेलकर घन नष्ट करना आदि अनेक ऐसी प्रवृत्तियां है जो न केवल निरर्थक है किन्तु वे अनेक आपदाओं को भी जन्म दे देती है।

ऐसी प्रवृत्तियां लोक जीवन में घर किये हुए हैं लाखों करोड़ों व्यक्ति आंख मूंद कर ऐसे अनावश्यक कार्यों में अपना तन मन और वन नष्ट कर रहे हैं। अनेक संघर्ष और तनाव जो मानव जीवन में व्याप्त है। उनमें से अधिकांश तो ऐसी निरर्थक बातों के कारण ही है। व्यक्ति अपने तनाव और चिन्ता से मुक्त होने के अनेक उपाय करता है। किन्तु अन्य कोई उपाय करने के पहले उसे अपने जीवन में से उन निरर्थक कार्यों को अलविदा कहना चाहिये जो उसके जीवन में व्यर्थ ही डेरा डाले हुए हैं और उसके तन मन को प्रदुषित कर रहे हैं। यदि जीवन में प्रवृत्तियों का निरर्थक अंश समाप्त हो जाता है और जीवन में सार स्वरुप आवश्यक कार्य विधियां ही शेष रहती है तो व्यक्ति के अधिकांश तनाव प्रकरण तो ऐसे ही समाप्त हो जायेंगे।

भगवान महावीर प्रभु ने मानव मात्र के लिये एक महत्व पूर्ण व्रत दिया है ‘अनर्थ दण्ड विरमणव्रत’ इस व्रत का विधान है जीवन में निरर्थक प्रवृत्तियों का त्याग करना। यदि राहड़ से अपने जीवन की समीक्षा करें तो इस व्रत की अप्रतिम विशेषता स्पष्ट परिलक्षित हो जाएगी क्योंकि जीवन निरर्थक प्रवृत्तियों से इस हद तक छया हुआ है कि साक्षर और उपयोगी प्रवृत्तियों के लिये व्यक्ति अपना समय ही नहीं दे सकता, कोई यह कहे कि व्यक्ति जो करता है उचित समझ कर ही करता है फिर वह निरर्थक कैसे ? इस प्रश्न के उत्तर के लिये फिर जीवन व्यवहार की गहराइयों में जाना होगा। उचित, आवश्यक समझकर जो किया वह बहुत कुछ निरर्थक ही सिद्ध हुआ इसलिए यह स्वीकार करना होगा कि अपना सोच ही सही नहीं है अतः वह निरर्थक प्रवृत्तियों को जन्म देता है। सोच की दिशा यथार्थवादी और तालिक होनी चाहिये। शुद्ध यथार्थवादी चिन्तन निरर्थक प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करके सार्वक उपयोगितावाद को स्थापित करेगा। एक प्रगतिशील जीवन के लिये सार्थक चिन्तन होना ही चाहिये।

सेवा और सहयोग नैतिक आचरण ही नहीं धार्मिकता भी है।

पीड़ित मानवता की सेवा मानव की उदात्त भावनाओं का परिणाम है; वे भावनाएं मात्र नैतिक आचरण ही नहीं है धार्मिकता भी है क्यों कि परोपकार का भाव और देय वस्तु के प्रति निर्ममलता का भाव आत्म भाव है। आत्म भाव में ही धर्म है। मानव के जन्म लेने के बाद जब तक वह जीवित रहता है तब तक प्रत्यक्ष और परोक्षरूप से हजारों व्यक्ति उसका सहयोग करते हैं जन सहयोग से ही मानव जीवन का विकास होता है।

उदाहरण स्वरुप समझिये कि एक बच्चा सड़क पर खेल रहा है और कोई वाहन तेजी से आ रहा है राह चलते व्यक्ति ने बच्चे को उठकर एक तरफ ले लिया बच्चा कुचल सकता था किन्तु दो अनजाने हाथोंने बचा लिया। यह कितना उपकार किया अन्त जाने हाथों ने, उनके सहयोग से जीवन बचगया। बचाने वाला नहीं जानता है कि किसे बचाया गया। और बचने वाला भी नहीं जानता कि उसे अनजाने हाथों से नव जीवन मिला है किन्तु मानवता की सेवा की एक महान घटना अचानक ही घटित हो गई। वह अभयदान सेवा इतना महत्व पूर्ण है कि उसकी तुलना किसी भौतिक पदार्थ से नहीं की जा सकती। करुणा और प्राणी रक्षा का भाव आना परम पवित्र आत्म भाव है। उक्त घटना से यह समझ में आजाना चाहिये कि अपना जीवन भी हजारों अनजाने हाथों के सहयोग से विकसित हुआ है। लोक जीवन के इस अवाय्छायित उपकार का ऋण हमे मानवता की सेवा कर के ही चुका सकते हैं।

सौरभ वाष्णेय

स्वास्थ्य किसी भी सभ्य समाज की बुनियादी आवश्यकता है और जीवन बचाने वाली दवाओं तक सुलभ पहुंच प्रत्येक नागरिक का अधिकार होना चाहिए। लेकिन जब बीमारी से जुड़ा रहा व्यक्ति इलाज के खर्च के सामने बेबस हो जाए, तब स्वास्थ्य व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की कीमतों में कथित भारी अंतर पर जो गंभीर चिंता जताई है, वह केवल दवा बाजार की अनियमितताओं का मामला नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य, सरकारी जवाबदेही और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा एक व्यापक प्रश्न है। अदालत के समक्ष कैसर के एक इंजेक्शन का उदाहरण आया, जिसकी कीमत लगभग ग्यारह हजार रुपये बताई गई, जबकि निजी अस्पताल में उसी इंजेक्शन के लिए डेढ़ लाख रुपये वसूले जाने की बात सामने आई। यदि इन आंकड़ों की पुष्टि होती है, तो यह अंतर निश्चित रूप से जांच और जवाबदेही की मांग करता है।

कैसर जैसी गंभीर बीमारी से जुड़ा रहे मरीज और उसके परिजन पहले ही मानसिक, शारीरिक बेदना सहित आर्थिक संकट से गुजरते हैं। ऐसे समय में इलाज का खर्च उनकी पेशानी को कई गुना बढ़ा देता है। परिवार अपनी बचत खर्च करता है, संपति बेचने को मजबूर होता है और कई बार उधार लेकर उपचार कराता है। यदि किसी दवा की खरीद कीमत और मरीज से वसूली जाने वाली राशि के बीच असमाधारण अंतर है, तो यह जानना आवश्यक है कि उस अंतर में दवा की वास्तविक लागत, अस्पताल का खर्च, भंडारण, आपूर्ति, कर, सेवा शुल्क और अन्य मदों का कितना योगदान है।

यह समझना भी जरूरी है कि दवा की निर्माता कीमत, वितरक की कीमत, अफिमत को खुदरा मूल्य एमआरपी और अस्पताल द्वारा मरीज से वसूली जाने वाली राशि हमेशा एक समान नहीं होती। अस्पताल में दवा देने, उसे

सुरक्षित रखने, निगरानी करने और उपचार संबंधी सेवाओं का खर्च भी हो सकता है। लेकिन इन खर्चों के नाम पर यदि बिना उचित आधार के कई गुना रकम वसूली जाती है, तो उसे सामान्य व्यावसायिक गतिविधि मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मरीज को स्पष्ट बिल, मूल्य का उचित विवरण और इलाज से संबंधित खर्चों की पारदर्शी जानकारी



मिलनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की भूमिका और दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

यह चिंता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दवाओं के मूल्य निर्धारण और आवश्यक औषधियों की उपलब्धता में सरकार की भूमिका निर्णायक होती है। जब बाजार में जीवनरक्षक दवाओं के दाम आम नागरिक की पहुंच से बाहर होने लगे, तब केवल नीतियां

बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की भी समीक्षा होनी चाहिए। भारत में आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश और राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

इनके माध्यम से निर्धारित दवाओं के मूल्य पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या निगरानी व्यवस्था मरीजों तक पर्याप्त राहत पहुंचा पा रही है? क्या मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर रहने वाली दवाओं और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले चिकित्सा उत्पादों की कीमतों पर पर्याप्त पारदर्शिता है? क्या नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध समय पर कार्रवाई होती है? इन सवालों के जवाब केवल सरकारी आंकड़ों से नहीं, बल्कि मरीजों के वास्तविक अनुभवों और स्वतंत्र जांच से भी मिलने चाहिए।

अदालत में सलाइन ड्रिप, हार्ट स्टेंट और एंटीबायोटिक जैसी वस्तुओं की कीमतों के उदाहरण भी सामने आए। बताया गया कि लगभग 11 रुपये की सलाइन ड्रिप 270 रुपये में, पांच हजार रुपये का हार्ट स्टेंट 25 हजार रुपये से अधिक में और 28 रुपये की एंटीबायोटिक एंजिथ्रोमाइसिन 70 रुपये से अधिक में बेची जा रही है। इन अकड़ों को

केंद्र सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि भारत में दवाओं की कीमतें दुनिया के कई देशों की तुलना में कम है। अंतरराष्ट्रीय तुलना अपने स्थान पर उपयोगी हो सकती है, लेकिन भारतीय मरीज की आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी दवा का दूसरे देश की तुलना में सस्ता होना अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसकी कीमत हर भारतीय परिवार की पहुंच में है। असली कसौटी यह होनी चाहिए कि मरीज को आवश्यक उपचार कितने खर्च में, कितनी आसानी से और कितनी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध हो रहा है।

सरकार को दवाओं की कीमतों और अस्पतालों में होने वाली वसूली की नियमित जांच के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद कीमत, मरीज से वसूली बड़ा अंतर पाया जाता है, तो नियामक संस्थाओं को उसका स्पष्ट कारण सामने रखना चाहिए।

विशेष रूप से हार्ट स्टेंट और कैसर के उपचार में उपयोग होने वाली दवाओं के मामले में मूल्य पारदर्शिता का महत्व और बढ़ जाता है। मरीज अक्सर चिकित्सक की सलाह पर निर्भर

वृहद भारत के शिल्पकार थे सरदार पटेल

सुरेश सिंह बैस ‘शाश्वत’

भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के इतिहास में सरदार वल्लभभाई पटेल का व्यक्तित्व अद्वितीय है। वे केवल स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी सेनानी नहीं थे, बल्कि स्वतंत्र भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक एकता के प्रमुख शिल्पकार भी थे। इसी कारण उन्हें 'लौह पुरुष' और आधुनिक भारत के एकीकरण के महान वास्तुकार के रूप में स्मरण किया जाता है।

सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उन्होंने कानून की शिक्षा लेकर सफल वकालत की, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद उनका जीवन पूरी तरह राष्ट्रसेवा को समर्पित हो गया। खेड़ा सत्याग्रह और विशेष रूप से 1928 के बारडोली सत्याग्रह में उनके प्रभावी नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और तभी उन्हें 'सरदार' की उपाधि मिली। पटेल का राजनीतिक जीवन केवल भाषणों तक सीमित नहीं था।

उन्होंने किसानों के बीच रहकर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। खेड़ा में लगान संबंधी समस्याओं और बारडोली में बंदे हुए भू-राजस्व के विरुद्ध उनके नेतृत्व ने ब्रिटिश प्रशासन को पीछे हटने के लिए विवश किया। वे महात्मा गांधी के निकटतम सहयोगियों में रहे

और असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन सहित स्वतंत्रता संघर्ष के अनेक चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी ,संगठन क्षमता, नियंत्र लेने का साहस और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ देश के सामने एक अत्यंत जटिल समस्या थी - रियासतों का एकीकरण। ब्रिटिश भारत के साथ-साथ देश में सैकड़ों देशी रियासतें थीं। ब्रिटिश सत्ता समाप्त होते ही इन रियासतों पर ब्रिटिश 'पैरामाउंटसी' भी समाप्त हो गई। परिणामस्वरूप भारत के राजनीतिक भविष्य के सामने यह गंभीर प्रश्न था कि ये रियासतें भारतीय संघ का हिस्सा बनेंगी या अलग-अलग रास्ता अपनाएंगी।

उस समय लगभग 565 देशी रियासतों का प्रश्न था। यदि वे अलग-अलग राजनीतिक इकाइयों के रूप में अस्तित्व बनाए रखतीं, तो भारत की भौगोलिक और राजनीतिक एकता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए 5 जुलाई 1947 को (राज्य विभाग) का गठन किया गया और सरदार पटेल ने इसका दायित्व संभाला। उनके साथ अनुभवी प्रशासक वी.पी. मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पटेल की प्रशासन को पीछे हटने के लिए विवश किया। वे महात्मा गांधी के निकटतम सहयोगियों में रहे

कठिन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। सरदार पटेल की सबसे बड़ी शक्ति केवल कठोरता नहीं थी। वे परिस्थितियों के अनुसार संवाद, समझाइश, राजनीतिक विश्वास और आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई, इन सभी का इस्तेमाल करना जानते थे। उन्होंने देशी रियासतों के शासकों से आग्रह किया कि वे अलग्नाव का रास्ता छोड़कर भारतीय संघ में शामिल हों। Instrument of Accession (विलय-पत्र) और Standstill Agreement के माध्यम से अनेक रियासतें भारतीय संघ में शामिल हुईं। पटेल ने शासकों को यह विश्वास भी दिलाया कि उनका सम्मान और कुछ वैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

14 अगस्त 1947 तक अधिकांश रियासतें भारत के साथ विलय के लिए सहमत हो चुकी थीं। हालांकि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर जैसी रियासतों की परिस्थितियां जटिल बनी रहीं। जूनागढ़ के मामले में जनमत भारत के पक्ष में था और फरवरी 1948 में हुए जनमत-संग्रह में भारी बहुमत ने भारत के साथ रहने का समर्थन किया। हैदराबाद में लंबे गतिरोध के बाद सितंबर 1948 में भारतीय कार्रवाई के पश्चात उसका भारत में विलय हुआ। जम्मू-कश्मीर का मामला पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण के बाद अलग परिस्थितियों में सामने आया और महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार पटेल

देश की अफसरशाही आखिर किसके लिए?

संजय कुमार शर्मा

देश की अफसरशाही आखिर किसके लिए काम करती है? आम आदमी के लिए, जिसकी गाढ़ी कमाई से सरकारी खजाना भरता है, या उन रसूखदार बिल्डों और पूंजीपतियों के लिए, जिनके हितों के सामने अक्सर जनहित गौण दिखाई देने लगता है? गाजियाबाद की गुलमोहर ग्रीन्स सोसाइटी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश ने एक बार फिर इन बुनियादी सवालों को देश के सामने खड़ा कर दिया है। जब नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़े और सरकारी तंत्र की भूमिका पर ही सवाल उठने लगे, तब यह मानने के पर्याप्त कारण पैदा होते हैं कि व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर खामी है।

नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक बिल्डर से जुड़े विवादों में न्यायपालिका की सख्ती के बाद भी यदि दूसरे विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, तो यह महज संयोग नहीं माना जा सकता। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और गुलमोहर ग्रीन्स सोसाइटी से जुड़ा विवाद भी इसी व्यापक समस्या की ओर ध्यान खींचता है। हालांकि किसी मामले में दोष और जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण न्यायालय के आदेश तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होना चाहिए, लेकिन बार-बार ऐसे विवाद सामने

आना सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही की पड़ताल जरूरी बनाता है।

आखिर किसके हितों की रक्षा कर रहा तंत्र?

विकास प्राधिकरणों की स्थापना शहरों को सुनियोजित बनाने, नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध बनाने और भवन निर्माण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इन संस्थाओं से अपेक्षा थी कि वे अवैध निर्माण, एक बार फिर इन बुनियादी सवालों को देश के सामने खड़ा कर दिया है। जब नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़े और सरकारी तंत्र की भूमिका पर ही सवाल उठने लगे, तब यह मानने के पर्याप्त कारण पैदा होते हैं कि व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर खामी है।

नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक बिल्डर से जुड़े विवादों में न्यायपालिका की सख्ती के बाद भी यदि दूसरे विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, तो यह महज संयोग नहीं माना जा सकता। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और गुलमोहर ग्रीन्स सोसाइटी से जुड़ा विवाद भी इसी व्यापक समस्या की ओर ध्यान खींचता है। हालांकि किसी मामले में दोष और जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण न्यायालय के आदेश तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होना चाहिए, लेकिन बार-बार ऐसे विवाद सामने

प्रश्नों का उत्तर केवल फाइलों और औपचारिक जांचों में नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में मिलना चाहिए। यह भी समझना होगा कि हर विवाद में बिल्डर और अधिकारी की मिलीभगत पहले से मान लेना उचित नहीं है। लेकिन जहां अनियमितताओं के आरोप हों, वहां निष्पक्ष जांच और पारदर्शी कार्रवाई से पीछे हटना भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। कानून का शासन तभी मजबूत होगा, जब प्रभावशाली लोगों और सामान्य नागरिकों के लिए एक ही नियम लागू होगा।

नोएडा से गाजियाबाद तक एक जैसी चिंता

नोएडा में सुपरटेक से जुड़े विवादों ने यह सवाल पहले ही गंभीर बना दिया है कि आखिर नियामक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी कितनी ईमानदारी से निभा रही हैं। जब किसी परियोजना में नियमों के उल्लंघन का मामला अदालत तक पहुंचता है और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है, तब संबंधित संबंधित बिल्डर को कठघरे में खड़ा करना पर्याप्त नहीं होता। यह भी जांचना जरूरी होता है कि मंजूरी देने, निगरानी करने और शिकायतों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों ने अपनी भूमिका किस तरह निभाई।

गाजियाबाद का मामला इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि विकास प्राधिकरण नागरिकों के हितों की रक्षा करने में विफल

रहते हैं, तो उसका खामियाजा उन परिवारों को भुगताना पड़ता है जिन्होंने अपनी पूरी बचत घर खरीदने में लगा दी। उनके लिए मकान महल क्यों रहते हैं? यदि किसी गरिब का मकान नियमों के उल्लंघन के नाम पर कार्रवाई की जद में आ सकता है, तो बड़े बिल्डों और उद्ध मंजूरी देने वाले अधिकारियों के मामले में भी कानून का समान रूप से पालन होना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली पारदर्शी हो, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो और हर स्वीकृति की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी पर तय हो। दोष साबित होने पर कार्रवाई भी ऐसी हो, जो भविष्य में दूसरे अधिकारियों के लिए चेतावनी बने। केवल जांच समितियां गठित करना और अदालती आदेशों का इंतजार करना पर्याप्त नहीं है। जनता को आश्वासन नहीं, जवाब चाहिए।

सरकारें निवेश, निर्माण और शहरी विकास को आर्थिक प्रगति का प्रतीक बताती हैं। इसमें संदेह नहीं कि निर्माण क्षेत्र रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन विकास का अर्थ केवल ऊंची इमारतें खड़ी करना नहीं है। विकास का वास्तविक मूल्य इस बात से तय होना चाहिए कि नागरिकों को सुरक्षित आवास, बुनियादी सुविधाएं और कानूनी संरक्षण कितना मिल रहा है। यदि चमकदार इमारतों के पीछे आम खरीदारों की पेशानी और प्रशासनिक जवाबदेही का अभाव छिपा हो, तो ऐसे विकास की अवधारणा पर पुनर्विचार आवश्यक है।

जनता की कमाई से चलने वाले तंत्र का हिसाब कौन लेगा? अफसरशाही की जवाबदेही का सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आम नागरिक सरकारी दफ्तरों में छोटें-छोटे कामों के लिए

होता है और उसे बाजार में विकल्पों की तुलना करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। ऐसे में उसकी मजबूरी का लाभ उठाने की किसी भी संभावना को रोकना सरकार, अस्पताल प्रशासन और नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी है। दवा उद्योग अनुसंधान, नई दवाओं के विकास, उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्पणियों को उचित लाभ कमाने का अधिकार है, लेकिन जीवनरक्षक दवाओं का बाजार सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार से अलग है। यहां ग्राहक के पास कई बार खरीद दलने या सस्ता विकल्प चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती। गंभीर बीमारी में दवा का विकल्प सीमित हो सकता है और उपचार में देरी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बाजार की शक्तियों के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व और प्रभावी सरकारी नियमन का संतुलन आवश्यक है।

केंद्र सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि भारत में दवाओं की कीमतें दुनिया के कई देशों की तुलना में कम है। अंतरराष्ट्रीय तुलना अपने स्थान पर उपयोगी हो सकती है, लेकिन भारतीय मरीज की आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी दवा का दूसरे देश की तुलना में सस्ता होना अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसकी कीमत हर भारतीय परिवार की पहुंच में है। असली कसौटी यह होनी चाहिए कि मरीज को आवश्यक उपचार कितने खर्च में, कितनी आसानी से और कितनी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध हो रहा है।

सरकार को दवाओं की कीमतों और अस्पतालों में होने वाली वसूली की नियमित जांच के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद कीमत, मरीज से वसूली बड़ा अंतर पाया जाता है, तो नियामक संस्थाओं को उसका स्पष्ट कारण सामने रखना चाहिए। विशेष रूप से हार्ट स्टेंट और कैसर के उपचार में उपयोग होने वाली दवाओं के मामले में मूल्य पारदर्शिता का महत्व और बढ़ जाता है। मरीज अक्सर चिकित्सक की सलाह पर निर्भर

बताना इतिहास को अत्यधिक सरल बना देगा। वह ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्षों में उभरते व्यापक अस्तोषण का एक महत्वपूर्ण संकेत था। INA के प्रभाव, नौसैनिक विद्रोह, युद्धोत्तर आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों और भारतीय जनमानस के बदलते रुख ने मिलकर ब्रिटिश शासन के सामने गंभीर चुनौती पैदा की।

सरदार पटेल को अक्सर 'लौह पुरुष' कहकर उनके व्यक्तित्व की कठोरता को रेखांकित किया जाता है, लेकिन उनका राजनीतिक कौशल केवल कठोर निर्णयों में नहीं था। वे गांधीजी की अहिंसक राजनीतिक रणनीति के महत्वपूर्ण सहयोगी थे और व्यापक ब्रिटिश राजनीति में समझौते, संवाद तथा संगठन की शक्ति को अच्छी तरह समझते थे। वे मानते थे कि स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी, जब भारत राजनीतिक रूप से संघटित, प्रशासनिक रूप से संक्षम और अंतिरिक्त रूप से मजबूत हो। इसी दृष्टि से उन्होंने स्वतंत्र भारत में अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्हें भारत के प्रशासनिक 'स्टील फ्रेम' को मजबूत करने वाले नेताओं में भी प्रमुख स्थान दिया जाता है।

स्वतंत्र भारत के निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की भूमिकाओं को परस्पर विरोध के रूप में देखना उचित नहीं है। दोनों के बीच अनेक मुद्दों पर मतभेद अवश्य थे, लेकिन स्वतंत्र भारत की नींव रखने में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

महीनों चक्कर काटता है, जबकि रसूखदारों के मामलों में नियमों की अनदेखी के आरोप सामने आते रहते हैं। आखिर यह दोहरा व्यवहार क्यों? यदि किसी गरिब का मकान नियमों के उल्लंघन के नाम पर कार्रवाई की जद में आ सकता है, तो बड़े बिल्डों और उद्ध मंजूरी देने वाले अधिकारियों के मामले में भी कानून का समान रूप से पालन होना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली पारदर्शी हो, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो और हर स्वीकृति की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी पर तय हो। दोष साबित होने पर कार्रवाई भी ऐसी हो, जो भविष्य में दूसरे अधिकारियों के लिए चेतावनी बने। केवल जांच समितियां गठित करना और अदालती आदेशों का इंतजार करना पर्याप्त नहीं है। जनता को आश्वासन नहीं, जवाब चाहिए।

महीनों चक्कर काटता है, जबकि रसूखदारों के मामलों में नियमों की अनदेखी के आरोप सामने आते रहते हैं। आखिर यह दोहरा व्यवहार क्यों? यदि किसी गरिब का मकान नियमों के उल्लंघन के नाम पर कार्रवाई की जद में आ सकता है, तो बड़े बिल्डों और उद्ध मंजूरी देने वाले अधिकारियों के मामले में भी कानून का समान रूप से पालन होना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली पारदर्शी हो, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो और हर स्वीकृति की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी पर तय हो। दोष साबित होने पर कार्रवाई भी ऐसी हो, जो भविष्य में दूसरे अधिकारियों के लिए चेतावनी बने। केवल जांच समितियां गठित करना और अदालती आदेशों का इंतजार करना पर्याप्त नहीं है। जनता को आश्वासन नहीं, जवाब चाहिए।

अदालत का चाबुक, लेकिन जवाबदेही कब तक? गुलमोहर ग्रीन्स मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो टावरों को पूरी तरह ध्वस्त करने और चार अन्य टावरों की नौतौं तथा दसवीं मंजिल गिराने का आदेश दिया है। प्राधिकरण को दो महीने में कार्रवाई पूरी करनी है। अदालत ने बिल्डर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना, प्राथमिकी दर्ज करने और तत्कालीन जीडीए उपाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश भी दिए हैं।

बुलंदशहर के छतारी में निर्माणाधीन दो मंजिला मकान ढहा

बुलंदशहर (एजेंसी) उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के कस्बा छतारी में शुक्रवार को दो मंजिला मकान ढह गया। इस घटना के बाद रहत और बचाव दलों ने एक महिला समेत तीन लोगों को बचा लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला की स्थिति सामान्य है। घायल पुरुषों को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बुलंदशहर में कस्बा छतारी में एक मकान बनाया जा रहा था, जो शुक्रवार रात करीब एक बजे अचानक से ढह गया। इस कारण एक महिला समेत तीन लोग मलबे में दब गए। घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस के साथ-साथ जिला प्रशासन, दमकल विभाग, सडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। घटना के संबंध में वित्त व राजस्व विभाग के एडीएम ने बताया कि रात करीब एक बजे थाना छतारी क्षेत्रान्तर्गत कस्बा छतारी में एक निर्माणाधीन मकान के ढह जाने और उसके मलबे में 3 व्यक्तियों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई थी।

वैज्ञानिक नवाचार से बिहार के विकास को मिलेगी नई गति : सीएम सम्राट चौधरी

ओपन सर्च. संवाददाता

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि अंतरिक्ष आधारित तकनीक, रिमोट सेंसिंग और वैज्ञानिक नवाचार राज्य के विकास को नई गति देने के साथ शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों से बिहार की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक एप्लीकेशन विकसित करने का आह्वान किया, ताकि उनका लाभ आम जनता, किसानों और प्रशासनिक व्यवस्था को मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस स्ट्रैटी, पटना में आयोजित दो दिवसीय ‘स्पेस एप्लीकेशन एडॉप्शन वर्कशॉप-2026’ को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रमाला की थीम ‘प्रगतिशील बिहार के लिए अंतरिक्ष आधारित समाधानों का उपयोग कर शासन को सशक्त बनाना’ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘टेककनेक्ट’ पोर्टल का

भाजपा की असली पूंजी सत्ता नहीं, कार्यकर्ता है, तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जुटे : पंकज चौधरी

विधानसभा चुनाव से पहले हो रही यह पहली प्रदेश कार्यसमिति संगठन के लिए महत्वपूर्ण है : पंकज चौधरी

लखनऊ (एजेंसी)

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाना है। शुक्रवार को लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में अपने अध्यक्षीय संबोधन में पंकज चौधरी ने कहा कि यह बैठक केवल औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि संगठन की ताकत का आकलन करने, सरकार की उपलब्धियों की समीक्षा करने और भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने का अवसर है।

पार्टी नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ 2027 के महासंग्राम में विजय का शंखनाद करने के लिए



एकत्र हुई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले हो रही यह पहली प्रदेश कार्यसमिति संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 14 जुलाई को इसी सभागार में कार्यकर्ता एकत्र हुए थे, लेकिन संगठनात्मक पुनर्गठन के बाद इस बैठक में नई प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य नई जिम्मेदारियों के साथ शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा

कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन और सबसे बड़ी पूंजी उसके कार्यकर्ता हैं। पार्टी की सफलता सत्ता से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और निरंतर परिश्रम से तय होती है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से बृथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने, नियमित बैठक करने और युवाओं, महिलाओं तथा नए मतदाताओं के बीच संगठन का

पंकज चौधरी ने कहा कि यह बैठक केवल औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि संगठन की ताकत का आकलन करने, सरकार की उपलब्धियों की समीक्षा करने और भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने का अवसर है

विस्तार करने का आह्वान किया। पंकज चौधरी ने कहा कि 2027 का चुनाव केवल राजनीतिक प्रतियुद्ध नहीं, बल्कि संगठनात्मक एकजुटता, जनसंवाद और सरकार के कामकाज की भी परीक्षा होगा।

चुनाव की तैयारी कुछ महीने पहले नहीं, बल्कि निरंतर जनता के बीच रहकर होती है। जनप्रतिनिधियों को संगठन के साथ नियमित संवाद बनाए रखना चाहिए और जनता की समस्याएं सुनकर उनके समाधान को प्राथमिकता देनी

बिहार: समस्तीपुर में फिलपकार्ट लूटकांड में छापेमारी के दौरान मुठभेड़, कुख्यात के पैर में लगी गोली, 2 गिरफ्तार

समस्तीपुर (एजेंसी)

समस्तीपुर जिले में गुरुवार देर शाम पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर में हुई मुठभेड़ के दौरान कुख्यात अपराधी मनीष कुमार सिंह के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के बाद घायल मनीष सिंह समेत दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। घायल अपराधी को पुलिस अभिरक्षा में समस्तीपुर सहर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

पुलिस के अनुसार मनीष सिंह के खिलाफ समस्तीपुर समेत चार जिलों में लूट, डकैती और आर्मस् एक्ट से जुड़े 28 से अधिक अपराधिक मामले दर्ज हैं। उम्र घटना के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई। सदर डीएसपी-1 सतीश सुमन के नेतृत्व में नगर, मुफरिसल और मुसरीघरारी थाने की पुलिस सदर



अस्पताल में तैनात रही। अस्पताल परिसर में एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार चार दिन पहले मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के हरपुर ऐलौथ स्थित फिलपकार्ट के क्षेत्रीय कार्यालय में हथियारबंद अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर करीब 1.49 लाख रुपये लूट लिए थे और वारदात के बाद कार्यालय में लगे सीसीटीवी सिस्टम का डीवीआर और हार्ड डिस्क भी उखाड़कर अपने साथ ले गए थे। इस लूटकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए समस्तीपुर पुलिस और एसटीोफ की टीम लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी।

यूपी पीईटी 2026 : पुलिस अधिकारियों ने पररवी परीक्षा की तैयारियां, केंद्रों पर सतर्कता के निर्देश



आयोग की ओर से यूपी पीईटी 2026 की परीक्षा आयोजित की जा रही है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा इंतजामों, पुलिस बल की तैनाती और ड्यूटी व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया।

साथ ही केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी की स्थिति का भी आकलन किया गया। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, असुविधा या कानून-व्यवस्था से जुड़ी

समस्या उत्पन्न न हो। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। उन्हें कहा गया कि परीक्षा केंद्रों के अंदर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए रखें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न करें।

सभी पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन पूरी मुस्तैदी, सतर्कता और निष्पक्षता के साथ करें। डीसीपी और एडीसीपी ने संबंधित

चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच मजबूत समन्वय ही भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यकर्ताओं को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सामाजिक समरसता और सर्वसमावेशी विकास को पार्टी की कार्यशैली का हिस्सा बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया।

प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2027 का चुनाव विकास बनाम विनाश और राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद की लड़ाई होगा। विपक्ष भ्रम और नकारात्मक आरोपों की राजनीति कर रहा है, जबकि भाजपा को अपनी उपलब्धियों और नीतियों के आधार पर जनता के बीच जाना है। उन्होंने पदाधिकारियों से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर संगठन की प्रतिष्ठ और अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की।

पूर्णिया : बेटी ने प्रेम विवाह किया तो भाई और पिता ने मरा मानकर किया श्राद्ध

पूर्णिया (एजेंसी)

कटिहार में प्रेम विवाह से नाराज एक परिवार ने ऐसा कदम उठाया, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। घरवालों की मर्जी के खिलाफ दूसरी जाति के युवक से शादी करना बेटी को इतना भारी पड़ा कि पिता और भाई ने उसे जीते-जी मृत मान लिया। परिवार ने बेटी का श्राद्ध कर्म कर भविष्य में उससे कोई रिश्ता नहीं रखने का फैसला कर लिया है। मामला कदवा थाना क्षेत्र के निझरा गांव का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांव के श्याम ठाकुर की बेटी ने परिवार की रजामंदी के बिना पहलागढ़ गांव के रहने वाले अजय पासवान से प्रेम विवाह कर लिया। अजय पासवान मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना पासवान के पुत्र बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बेटी के इस फैसले से उसके घरवाले बेहद नाराज हैं। परिवार की नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने बेटी को अपने परिवार से अलग मानते

यूपी की कानून-व्यवस्था पर सीएम योगी बोले- ‘हमारी बेटियां सुरक्षित वातावरण में, डबल इंजन सरकार ने बदली परिस्थिति’

लखनऊ (एजेंसी)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कहा है कि आज बाजार रात में भी खुले रहते हैं। व्यापारियों को व्यवसाय के विस्तार के नए अवसर मिल रहे हैं और हमारी बेटियां सुरक्षित वातावरण में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने इस परिस्थिति को बदला। यूपी की कानून-व्यवस्था पर सीएम योगी बोले- ‘हमारी बेटियां सुरक्षित वातावरण में, डबल इंजन सरकार ने बदली परिस्थिति’

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, आज नए उत्तर प्रदेश में रात्रि के समय जगमगाते बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की रोशनी केवल व्यापार की नहीं, बल्कि व्यापारी के विश्वास का प्रकाश है।

नाइट शिफ्ट में अपने कार्यस्थल पर निर्भय होकर दायित्व निभाती हमारी मातृशक्ति का आत्मविश्वास केवल व्यक्तितगत उपलब्धि नहीं,



बल्कि पूरे समाज की प्राप्ति का प्रतीक है। उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, ‘किंतु सुरक्षा और विश्वास का यह वातावरण उत्तर प्रदेश में सदैव नहीं था। वर्ष 2017 से पहले अपराध और असुरक्षा के कारण सूर्यास्त के साथ व्यापारिक गतिविधियां सीमित होने लगती थीं। देर रात तक कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर परिवारों में चिंता बनी रहती थी। सीएम योगी ने आगे कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने इस परिस्थिति को बदला। अपराध और अपराधियों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किया एवं महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी। आज बाजार रात में भी खुले रहते हैं।



हुए उसका श्राद्ध कर्म कर दिया। साथ ही भविष्य में उससे किसी तरह का संबंध नहीं रखने की बात भी कही जा रही है। एक तरफ बेटी ने अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया तो दूसरी तरफ उसके इस कदम से नाराज परिवार ने उससे नाता तोड़ने का रास्ता चुन लिया।

इस घटनाक्रम ने गांव में नई चर्चा छेड़ दी है। पिता श्याम ठाकुर का कहना है कि मेरी बेटी दूसरे के साथ भाग गई और मेरा प्रतिष्ठ का तार-तार कर दिया। इसलिए मेरे लिए वो मर गई, मैंने उसका अंतिम संस्कार करके और पिंड दान कर दिया। वहीं बेटी

सेजल का कहना है कि मैं और अजय 11 साल से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। हमने अपने घरवालों को शादी के लिए राजी करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मानने पर हमें यह कदम उठाना पड़ा। सेजल ने कहा कि मैं अपने पति के साथ खुश हूं और कोई मेरा अपहरण नहीं किया गया है। बहरहाल इस मामले को लेकर इलाके में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रेम विवाह के बाद परिवार की ओर से उड़ाए गए इस कदम से सामाजिक परंपराओं, जातिगत बंधनों और व्यक्तिगत फैसलों को लेकर बहस छेड़ दी है।

पटना में सड़क पर उतरे अभाविप के कार्यकर्ता, ‘लोकतंत्र बचाने और अराजकता रोकने की अपील

पटना (एजेंसी)

पटना में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) का विशाल विरोध प्रदर्शन जारी है। ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता रोको’ के आह्वान पर परिषद के कार्यकर्ता और विद्यार्थी सड़क पर उतरकर मार्च निकाल रहे हैं। प्रदर्शन गांधी मैदान से शुरू होकर इनकम टैक्स चौराहे तक जा रहा है। अभाविप का कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, गरिमा और मर्यादा का सम्मान जरूरी है।

संगठन इस प्रदर्शन के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संदेश दे रहा है। अभाविप बिहार प्रदेश के प्रदेश मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि लोकतंत्र केवल शासन चलाने की संदेश समाज तक पहुंचाएगी।

23वीं मंजिल से गिरकर पिता और पुत्र की मौत, पूजा के लिए बालकनी से तोड़ रहे थे फूल

ग्रेटर नोएडा (एजेंसी)

ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित महापुत्र मायवुड्स सोसायटी में शुक्रवार सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। सोसायटी की 23वीं मंजिल से गिरकर पिता और उनके 11 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पिता अपने बेटे के साथ बालकनी में पूजा के लिए फूल तोड़ रहे थे। इसी दौरान अचानक बेटे का पैर फिसल गया और वह बालकनी से नीचे की ओर लटक गया। बेटे को बचाने की कोशिश में पिता भी संतुलन खो बैठे और दोनों नीचे जा गिरे। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सोसायटी में अपराध-तफरी मच गई और परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार 30 अक्टूबर 2026 को थाना बिसरख



को पीआरवी के माध्यम से सूचना मिली कि महापुत्र मायवुड्स सोसायटी के टॉवर-23 में ऊंचाई से गिरने के कारण दो लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची।

वहां रणदीप पात्रा (करीब 40 वर्ष) पुत्र अमल कुमार पात्रा और उनके 11 वर्षीय बेटे आरव को गंभीर अवस्था में पाया गया। पुलिस ने बिना देरी किए दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को दिए गए बयान में मृतक रणदीप की पत्नी

ने बताया कि शुक्रवार सुबह उन्हें खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए जल्दी निकलना था। इसी वजह से उनके पति और बेटा सुबह पूजा के लिए बालकनी से फूल तोड़ने गए थे। इसी दौरान सीढ़ी से पैर फिसलने के कारण दोनों बालकनी से नीचे गिर गए। हालांकि, हादसे के वास्तविक कारणों और घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि बेटे का पैर फिसलने के बाद वह बालकनी से नीचे की ओर लटक गया था। उसे बचाने के लिए पिता ने तत्काल प्रयास किया, लेकिन इस दौरान वह भी अपना संतुलन खो बैठे। देखते ही देखते दोनों 23वीं मंजिल से नीचे जा गिरे। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण दोनों को गंभीर चोटें आईं और उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

अमेरिकी जनगणना रिपोर्ट : भारतीय मूल के अमेरिकियों की संख्या 5.4 मिलियन के पार

वाशिंगटन (एजेंसी)

अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा जारी ‘अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे’ (एसीएस) के नए 1-वर्षीय अनुमानों के अनुसार, 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका में खुद को केवल भारतीय अमेरिकी मानने वाले लोगों की संख्या बढ़कर लगभग 54.1 लाख (5.41 मिलियन) हो गई है। ब्यूरो की एशियाई समूहों से जुड़ी विस्तृत तालिका के अनुसार, यह आंकड़ा 2024 के लगभग 50.9 लाख (5.09 मिलियन) से बढ़कर 2025 में 54.1 लाख (5.41 मिलियन) हो गया है, जो एक साल में 3,15,000 से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

2025 के इस अनुमान में लगभग 77,000 का मार्जिन ऑफ़ एरर (त्रुटि की गुंजाइश) भी शामिल है। यदि उन लोगों को भी शामिल किया जाए जिन्होंने खुद को एशियाई भारतीय बताया है- चाहे वे केवल भारतीय हों या किसी अन्य समूह या नस्ल से जुड़े



हों, तो यह कुल संख्या बढ़कर लगभग 59.1 लाख (5.91 मिलियन) हो जाती है, जो एक साल पहले लगभग 55.6 लाख (5.56 मिलियन) थी। इस तरह, एशियाई भारतीय सबसे बड़ा एकल एशियाई समूह बन गए हैं। इस मामले में वे चीनी (ताइवानी को छोड़कर) लोगों से आगे हैं, जिनकी संख्या लगभग 46.5 लाख (4.65 मिलियन) है। यदि अन्य समूहों के साथ उनके जुड़वा को भी शामिल कर लिया जाए, तो चीनी (ताइवानी को

छोड़कर) लोगों की संख्या लगभग 59.7 लाख (5.97 मिलियन) हो जाती है, जो एशियाई भारतीयों की कुल संख्या के लगभग बराबर है। सर्वे के अनुसार, 2025 में अमेरिका की कुल जनसंख्या लगभग 34.18 करोड़ (341.8 मिलियन) थी। सर्वे से यह भी पता चला है कि अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों के जन्मस्थान के मामले में, मैक्सिको के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। 2025 में अमेरिका में रहने वाले लगभग 34

ब्यूरो की एशियाई समूहों से जुड़ी विस्तृत तालिका के अनुसार, यह आंकड़ा 2024 के लगभग 50.9 लाख (5.09 मिलियन) से बढ़कर 2025 में 54.1 लाख (5.41 मिलियन) हो गया है, जो एक साल में 3,15,000 से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। 2025 के इस अनुमान में लगभग 77,000 का मार्जिन ऑफ़ एरर (त्रुटि की गुंजाइश) भी शामिल है।

लाख (3.40 मिलियन) लोग भारत में जन्मे थे, जबकि 2024 में यह संख्या लगभग 31.6 लाख (3.16 मिलियन) थी। मैक्सिको में जन्मे लोगों की संख्या लगभग 1.06 करोड़ (10.61 मिलियन) थी। भारत के बाद चीन (होंगकॉंग और ताइवान को छोड़कर) का स्थान है, जहां से लगभग 24 लाख (2.40 मिलियन) लोग आए हैं और फिर फिलीपींस का नंबर आता है, जहां से लगभग 22.4 लाख (2.24 मिलियन) लोग आए हैं। अमेरिका में रहने वाली कुल विदेशी मूल की आबादी लगभग 5.04 करोड़ (50.41 मिलियन) थी। कैलिफ़ोर्निया में भारतीय मूल के

लोगों की आबादी सबसे ज्यादा (लगभग 10.2 लाख) थी। इसके बाद टेक्सास (लगभग 7.08 लाख), न्यू जर्सी (लगभग 4.71 लाख), न्यूयॉर्क (लगभग 4.2 लाख) और इलिनोइस (लगभग 2.88 लाख) का नंबर आता है।

फ्लोरिडा लगभग 2.39 लाख की आबादी के साथ छठे स्थान पर रहा। एसीएस के आंकड़ों से परिवारों की आय में बढ़ोतरी का भी पता चला। 2025 में परिवारों की राष्ट्रीय मीडियन (मध्य) आय 84,780 डॉलर थी, जबकि 2024 में यह 81,604 डॉलर थी। जनगणना ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े

नए आंकड़े भी जारी किए। ब्यूरो के अनुसार, कैलिफ़ोर्निया में सबसे ज्यादा (लगभग 14 प्रतिशत) ऐसे परिवार थे जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन (खरीदा हुआ या लीज पर लिया हुआ) था। यह आंकड़ा 5.5 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से दोगुने से भी ज्यादा है। जनगणना ब्यूरो की सर्वेक्षण सांख्यिकीविद् ट्रिशिया होली ने कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में पश्चिमी राज्यों ने सबसे आगे बढ़कर काम किया है।

कैलिफ़ोर्निया में प्रति परिवार इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की दर सबसे ज्यादा रही, जिसके बाद वाशिंगटन, हवाई और नेवादा का स्थान आता है। उन्होंने आगे कहा, अगर हम काउंटी (जिले) के स्तर पर देखें, तो कैलिफ़ोर्निया की सांता क्लारा काउंटी देश में सबसे आगे है, जहाँ लगभग 24 प्रतिशत परिवारों के पास इलेक्ट्रिक वाहन है। सिलिकॉन वैली का ज्यादातर टेक्नोलॉजी उद्योग सांता क्लारा काउंटी में ही स्थित है।

भूटान की हिमनद झील के फटने से बंगाल-असम में बाढ़ की चेतावनी, प्रशासन सतर्क

थिम्पू (एजेंसी)

उत्तर-पश्चिमी भूटान में शिंताफू झील के फटने से पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारी इन दोनों राज्यों की ओर बहने वाली नदियों के किनारे स्थित स्वेदरशील इलाकों पर नजर रख रहे हैं। यह घटना गुरुवार शाम भूटान के गासा जिले में हुई। इससे गासा त्साचू में मौजूद बुनियादी ढांचा बह गया। गासा त्साचू, मो छू नदी के पास स्थित एक लोकप्रिय प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है। बाढ़ का पानी पहुँचने से पहले ही इस इलाके को खाली करा लिया गया था, इसलिए किसी के हाताहत होने की कोई खबर नहीं है। मो छू नदी के उद्गम स्थल पर स्थित शिंताफू झील, भूटान की उन 17 हिमनद झीलों (स्लेशियल लेक्स) में



से एक है, जिन्हें संभावित रूप से खतरनाक माना गया है। इससे पहले 26 अगस्त 2021 को भी गासा त्साचू को अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान पहुंचा था, जब उफान पर बह रही मो छू नदी ने अपना रास्ता बदलकर गर्म पानी के स्रोत की ओर रुख कर लिया था।

रिपोर्टों के अनुसार, बाढ़ का पानी पुराखा जोंग से लगभग आठ किलोमीटर दूर, काबेसा गेवोग के श्रीगंग इलाके से आगे निकल गया है, जिससे नदी के निचले इलाकों को लेकर चिंता बढ़ गई है। भूटान ने पश्चिम बंगाल और असम के प्रशासन को इस

हिमालयी देश की सीमा से लगे जिलों के लिए संभावित खतरे के बारे में सतर्क कर दिया है। असम का धुबरी जिला और पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियां, अलीपुरद्वार तथा जलपाईगढ़ी को संवेदनशील इलाकों के रूप में चिह्नित किया गया है। पश्चिम बंगाल में, कूच बिहार प्रशासन ने संकोश नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्क कर दिया है। यह नदी उत्तरी भूटान से निकलती है और उस नदी प्रणाली का हिस्सा है, जो हिमालयी क्षेत्र से पानी को असम में ब्रह्मपुत्र नदी तक पहुंचाती है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। अलीपुरद्वार जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमित कुमार शां ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है।

जम्मू-कश्मीर : पुलिस ने शोपियां में जेल से जुड़े आतंकी फंडिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 10 आरोपी गिरफ्तार

श्रीनगर (एजेंसी)

पुलिस ने शुक्रवार को शोपियां में बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल से जुड़े आतंकी फंडिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इस दौरान 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आतंकी इकोसिस्टम के खिलाफ शोपियां पुलिस ने आतंकी गतिविधियों से जुड़े सख्तिब वित्तीय नेटवर्कों की गहन जांच के बाद जम्मू-कश्मीर में काम करने वाले एक ‘टेरर फाइनेंसिंग’ (आतंकी फंडिंग) मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

जांच के दौरान, विभिन्न पेंमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए किए गए सख्तिब ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण किया गया, जिससे पैसों के लेन-देन के कई स्तरों का पता चला। जांच में अलग-अलग जेलों में बंद आतंकवादियों और उनके साथियों के आतंकी फंडिंग में शामिल होने का खुलासा हुआ है। इस मामले

में अब तक आतंकवादियों के 10 सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके तहत, शोपियां पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफ.आई.आर दर्ज की गई है। पुलिस ने ओसेस शफी नाइकू, तजामुल अहमद शाह, मोइज इकबाल, इमदाद यूसुफ गनी, साकिब जहूर वानी, आमिर अहमद गनी, फिरोदोस ठोकर, लियाकत नजीर लोन, मोहम्मद हनीफ और काजू को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी गुप्त रूप से आम जनता से फंड इकट्ठा कर रहे थे और स्थापित वित्तीय माध्यमों के जरिए इस पैसे को लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी गतिविधियों के लिए पहुंचा रहे थे। आरोप है कि इन फंड का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट (जिसमें स्मार्टफोन भी शामिल हैं) मुहैया कराने में किया जा रहा था।

लेखक गांव, समाज को दिशा देने वाले विचारों का प्रतीक है : मुख्यमंत्री पुष्कर धामी



ओपन सर्व/ओ पी उनियाल

देहरादून। आज लेखक गांव, थानो में आयोजित लेखक गांव अंतरराष्ट्रीय महोत्सव- 2026 का समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लेखक गांव की पत्रिका ‘धरती का स्वर्ग उत्तराखण्ड’ एवं ‘देवभूमि का काव्य पुष्प’ पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखक गांव, समाज को दिशा देने वाले विचारों का प्रतीक है। जो वर्तमान के साथ भविष्य का निर्माण कर रहा है। लेखक गांव, प्रदेश में स्थानीय प्रतिभाओं को नया मंच देने के साथ साहित्यिक मानचित्र पर राज्य

को नई पहचान दे रहा है। उन्होंने भारत रत्न स्वर. अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि वह शब्दों के साधक थे, उनकी लेखनी में पर्वतों सी दृढ़ता और गंगा सी गहराई थी। अटल जी ने हमें सिखाया कि शब्द भी राष्ट्र निर्माण के शस्त्र बन सकते हैं।

उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड हमेशा से रचनात्मकता, ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रही है। देवभूमि से निकले विचारों ने हमेशा समाज को प्रेरित और आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तराखण्ड में ऋषियों के अनेक महान ग्रंथों की रचना की। देवभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य ने हमेशा लेखकों, कवियों और विचारकों को

प्रेरित करने का काम किया है। साहित्य ही हमारे मूल्यों और विचारों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखकों, कवियों और रचनाकारों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान भी लेखकों, साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया। लेखक और रचनाकार शब्दों के निर्माता के साथ समाज के चिंतक, मार्गदर्शक भी होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रही है। राज्य में उत्तराखण्ड साहित्य गोष्ठय सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट एवम पुरस्कारों के माध्यम से प्रदेश के उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित किया जा रहा है। वहीं हिंदी सहित विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए साहित्यकारों को अनुदान भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार उत्तराखण्ड को साहित्यिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र रूप में विकसित करने के लिए भी कार्य कर रही है।

पश्चिम बंगाल : 280 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की चार जगहों पर छापेमारी



मौजूद थे। सुदीप्तो घोष पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसके परिवार से पूछताछ की जा रही है और उसके घर की तलाशी ली जा रही है। हालांकि, सुदीप्तो घोष का कहना है कि उसका

इस भ्रष्टाचार के मामले से कोई लेना-देना नहीं है। जांचकर्ताओं ने जांच के लिए अनुमति ले ली है और सुदीप्तो घोष केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा है। ईडी के अधिकारियों ने लेक टाउन स्थित पॉश ‘अवनी ऑक्सफोर्ड (फेज 1)’ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में चार्टर्ड



अकाउंटेंट (सीए) अशोक सारथी के घर पर भी छापेमारी की। वहां सुबह से ही केंद्रीय बलों की कड़ी सुरक्षा के बीच सचन तलाशी अभियान और पूछताछ चल रही है।

जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, यह छापेमारी झारखंड में पावर प्रोजेक्ट या पावर प्लांट बनाने के नाम पर बैंक से ली गई रकम में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत की जा रही है। जांच के दायरे में आई मुख्य निजी कंपनी का नाम ‘कोहिनूर पावर प्राइवेट

मुंबई इंडियंस ने कोचिंग सेटअप को दिया ‘नया लुक’, पोलार्ड के बाद उथप्पा, मैक्लेनेघन, दिलीप और कुलकर्णी की एंट्री

मुंबई (एजेंसी)

मुंबई इंडियंस (एमआई) ने शुक्रवार को आईपीएल 2027 के लिए रॉबिन उथप्पा को बैटिंग कोच, मिशेल मैक्लेनेघन को गेंदबाजी कोच, टी. दिलीप को फील्डिंग कोच और धवल कुलकर्णी को डेवलपमेंट गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। रॉबिन उथप्पा, मिशेल मैक्लेनेघन और धवल कुलकर्णी पूर्व में मुंबई इंडियंस के लिए लंबे समय तक खेल चुके हैं।

मिशेल मैक्लेनेघन का गेंदबाजी कोच के रूप में स्वागत करते हुए एमआई ने एक्स पर लिखा, हमें मिच वापस मिल गया। एक फैन फेवरेट जिसने अपनी एमआई का बैज पहना और एमआई स्पिरिट को दिखाया। घर में स्वागत है, मिशेल मैक्लेनाघन। न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिशेल मैक्लेनेघन ने 2015 से 2019 तक 56 मैच खेले, जिसमें 71 विकेट हासिल किए। इस दौरान एमआई 2015, 2017 और 2019 में विजेता रही थी। एमआई ने भारतीय टीम के पूर्व फील्डिंग कोच टी. दिलीप को अपना फील्डिंग कोच बनाया है। टी. दिलीप भारत के सफलतम



फील्डिंग कोच रहे हैं। दिलीप का स्वागत करते हुए एमआई ने एक्स पर लिखा, भारत के साथ तीन आईसीसी खिताब से लेकर मेडल सेरेमनी के यादगार पलों तक, टी. दिलीप ने अपनी ऊर्जा और पैशन से फैंस का दिल जीता है। अब, वह हमारे फील्डिंग कोच के तौर पर पलटन में भी वही जोश लाते हैं। एमआई ने पूर्व तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी

को डेवलपमेंट गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। एक्स पर कुलकर्णी का स्वागत करते हुए एमआई ने लिखा, मुंबई के अपने, घरेलू टीम के दिग्गज, और अब हमारे डेवलपमेंट बॉलिंग कोच।

वापसी पर स्वागत है, धवल कुलकर्णी। धवल कुलकर्णी 2007 से 2013 और 2020 से 2021 तक एमआई का हिस्सा रह चुके हैं। इस

दौरान उन्होंने 35 मैचों में 36 विकेट लिए। इसके अलावा, वह गुजरात लायंस और राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेल चुके हैं।

एमआई ने पूर्व भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को अपना बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। वह 2007 में टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। रॉबिन ने 2008 में अपने आईपीएल

करियर का आगाज एमआई से ही किया था। वह आईपीएल के सफलतम बल्लेबाजों में से एक हैं। कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) को 2014 में चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले रॉबिन 2021 में लीग जीतने वाली चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के सदस्य रहे थे। 2008 से 2022 के बीच रॉबिन उथप्पा ने मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पुणे वॉरियर्स इंडिया, केकेआर, राजस्थान रॉयल्स और सीएसके के लिए खेले हैं। कुल 205 मैचों की 197 पारियों में इस आक्रामक बल्लेबाज ने 27 अर्धशतक लगाते हुए 4,952 रन बनाए थे।

मिशेल मैक्लेनेघन, टी. दिलीप, धवल कुलकर्णी और रॉबिन उथप्पा की नियुक्ति के साथ ही आईपीएल 2027 के लिए मुंबई इंडियंस का कोचिंग सेटअप पूरा हो गया है, जो पूरी तरह नया है। बता दें कि एमआई ने कुछ समय पहले ही कीरोन पोलार्ड को हेड कोच के रूप में नियुक्त किया था। पोलार्ड एमआई के साथ 2010 से 2022 तक खिलाड़ी और उसके बाद 2026 तक बैटिंग कोच के रूप में जुड़े रहे।

आईपीएल में खिलाड़ी और कोच के रूप में एमआई के साथ डेब्यू किस्मत की बात : उथप्पा



मौका पाकर बहुत खुश हूं। सच कहूं तो यह किस्मत जैसा लगता है।

मैंने अपना आईपीएल करियर मुंबई इंडियंस के साथ शुरू किया था और मैं अपना आईपीएल कोचिंग करियर भी मुंबई इंडियंस के साथ शुरू कर रहा हूं। उथप्पा ने कहा, ‘2008 में, जब मैं फ्रेंचाइजी में आया, मुझे

यاد है कि हम ऑस्ट्रेलिया में थे, ऑस्ट्रेलिया में सीबी सीरीज खेल रहे थे, जब ऑक्शन हुए, और मुझे पता था कि मैं अपने हीरो, सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने वाला हूं। तो मेरे लिए, वो समय सच में बहुत उत्साहपूर्ण था। उस पहले सीजन में हर कोई अपनी जगह बना रहा था। इसमें फ्रेंचाइजी, खिलाड़ी, टीमें और लीग भी शामिल थीं। उन्होंने कहा, मैं कहूंगा, काफी अच्छा सीजन था, और बेहतर हो सकता था। हमें चोटें लगीं, और सचिन तेंदुलकर उस टूर्नामेंट का एक बड़ा हिस्सा चूक गए। हरभजन सिंह ने फिर कप्तानी की। समथ जयसूर्या और शॉन पोलक ने बहुत अच्छा खेला था। उथप्पा ने कहा, मैंने मुंबई को फैंस का भरोसा और विश्वास जीतते हुए, चैंपियन बनते हुए, और फिर लगातार जीतते हुए और जीतने के नजरिए से दुनिया की सबसे अच्छी फ्रेंचाइजी में से एक बनते हुए देखा है।

फुटबॉल : जापान और सिंगापुर के खिलाफ मैच के लिए ब्राजील की टीम में पांच अनकैण्ड खिलाड़ियों को मौका रियो डी जनेरियो (एजेंसी)



जापान और सिंगापुर के खिलाफ होने वाले मैत्री मैचों के लिए ब्राजील की घोषित टीम में नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। मैनचेस्टर सिटी के फॉर्वरड एलन एलियास उन पांच अनकैण्ड खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें पहली बार मौका मिला है। 26 सदस्यीय टीम में शामिल अन्य नए खिलाड़ियों में क्रूजेरो के डिफेंडर जोनाथन जीसस, कोरिथियंस के मिडफील्डर आंद्रे लुइज और शाख्तर डोनेट्स्क की जोड़ी मार्लन गोम्स और एलिसन सैन्ताना शामिल थे। ब्राजील के मैनेजर कार्लो एसेलोटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हर खिलाड़ी की अपनी अलग-अलग खूबियां होती हैं। जोनाथन जीसस मुझे बहुत मजबूत, बहुत तेज, आक्रामक और बुद्धिमान सेंटर-बैक लगते हैं। मार्लन गोम्स में बहुत जोश है। वे अलग-अलग खूबियों वाले फुटबॉलर हैं। हमारे लिए एक एक को बेहतर तरीके से जानना बहुत जरूरी है। ब्राजील 14 नवंबर को जापान से और तीन दिन बाद

के साथ की थी और सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे क्रिकेट में 15,000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने थे। इसके बाद उन्होंने दूसरे मैच में 29 रन बनाए, जबकि आखिरी मुकाबले में वह खाता भी नहीं खोल पाए थे। वर्तमान में दुनिया के नंबर-3 वनडे बल्लेबाज कोहली का न्यूजीलैंड में रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने वहां 13 पारियों में 49.66 की औसत और 91.41 के स्ट्राइक रेट से 596 रन बनाए हैं, जिसमें चार अर्धशतक और एक शतक (2014 में नैपियर में 123 रन) शामिल है। बीसीसीआई ने इस पांच मैचों की सीरीज के लिए दो अलग स्क्वाड घोषित किए हैं। शुरुआती तीन वनडे मैचों में शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि आखिरी दो मैचों की कप्तान थ्रेयस अय्यर संभालेंगे।

अर्शदीप 150 अंतरराष्ट्रीय टी20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने, तोड़ा हसरंगा का रिकॉर्ड

ऑकलैंड (एजेंसी)

भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शुक्रवार को ईडन पार्क में न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच के दौरान अपने 150 विकेट किए। वह अंतरराष्ट्रीय टी20 में 150 विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज हैं। अर्शदीप ने न्यूजीलैंड की पारी के 19वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटरन को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की।

अर्शदीप ने डेब्यू के बाद सबसे कम दिन में टी20 आई, में 150 विकेट लिए हैं। नवंबर 2022 में अपना टी20 डेब्यू करने वाले अर्शदीप ने 1577 दिनों में 150 टी20 विकेट पूरे किए। डेब्यू के बाद सबसे तेज 150 विकेट तक पहुंचने वाले पिछले खिलाड़ी का रिकॉर्ड



श्रीलंका के वांिनंदु हसरंगा के नाम था। हसरंगा ने 2325 दिनों में अपने 150 विकेट पूरे किए थे। बाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज गेंदों के हिसाब से 150 विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर है। अर्शदीप ने 2143 दिनों में यह उपलब्धि हासिल की है। हसरंगा (2035 गेंदें) पहले और राशिद खान

(2098) दूसरे नंबर पर हैं। अर्शदीप सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज भी बन गए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को पीछे छोड़ा। अर्शदीप ने फुल-मैचर देशों के खिलाड़ियों द्वारा एक साल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी

अपने नाम किया। इस गेंदबाज ने 2026 में अब तक 40 विकेट लिए हैं। अर्शदीप ने जोश लॉटिल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नाम 2022 में 39 विकेट लेने का रिकॉर्ड था।

अर्शदीप के नाम अब 103 मैचों में 150 विकेट हो गए हैं। वह इस फॉर्मेट में भारत के सफलतम गेंदबाज हैं। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय टी20 विकेट अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम है। राशिद ने 119 मैचों में 199 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड के आदिल राशिद 153 मैचों में 171 विकेट लेकर दूसरे, हांगकांग के एहसान खान 119 मैचों में 165 विकेट लेकर तीसरे, न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी 142 मैचों में 165 विकेट लेकर चौथे, न्यूजीलैंड के ही टिम साउडी 126 मैचों में 164 विकेट लेकर पांचवें स्थान पर हैं।

भारत बनाम न्यूजीलैंड : वनडे सीरीज के लिए ऑकलैंड पहुंचते विराट कोहली, एयरपोर्ट पर जुटी भारी भीड़

ऑकलैंड (एजेंसी)

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले विराट कोहली के ऑकलैंड पहुंचने पर एयरपोर्ट पर प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद भारत के स्टार बल्लेबाज को देखने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए फैंस बेताब दिखे।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में समर्थक बैरिकेड्स के पीछे खड़े होकर कोहली का नाम लेते और तस्वीरें लेते नजर आए। कुछ फैंस ने उनके जन्मदिन के लिए एडवॉंस में शुभकामनाएं देने वाले पोस्टर भी ले रखे थे। भीड़ के उत्साह को शांत करने के लिए कोहली ने हाथ उत्कार लोगों से संयम बताने का इशारा किया। इस दौरान एक बेहद उत्सुक प्रशंसक



लगातार ऑटोग्राफ की मांग कर रही थी, जिस पर भारतीय बल्लेबाज ने पहले उन्हें शांत रहने को कहा और फिर उनका पोस्टर साइन किया। अंत में सुरक्षाकर्मियों की मदद से वह भीड़ के बीच से बाहर निकल पाए। 37 वर्षीय कोहली शुक्रवार को ऑकलैंड पहुंचे और भारतीय वनडे स्क्वाड से जुड़ गए हैं। यह सीरीज चार नवंबर से ईडन पार्क में शुरू होगी।

उनके साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा एक दिन पहले ही ऑकलैंड पहुंच चुके थे, जबकि टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल भी टीम के साथ जुड़कर नेट्स में अभ्यास कर रहे हैं। इस सीरीज से पहले कोहली ने घर में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने सीरीज की शुरुआत 88 गेंदों में नाबाद 139 रनों की पारी

के साथ की थी और सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे क्रिकेट में 15,000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने थे। इसके बाद उन्होंने दूसरे मैच में 29 रन बनाए, जबकि आखिरी मुकाबले में वह खाता भी नहीं खोल पाए थे। वर्तमान में दुनिया के नंबर-3 वनडे बल्लेबाज कोहली का न्यूजीलैंड में रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने वहां 13 पारियों में 49.66 की औसत और 91.41 के स्ट्राइक रेट से 596 रन बनाए हैं, जिसमें चार अर्धशतक और एक शतक (2014 में नैपियर में 123 रन) शामिल है। बीसीसीआई ने इस पांच मैचों की सीरीज के लिए दो अलग स्क्वाड घोषित किए हैं। शुरुआती तीन वनडे मैचों में शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि आखिरी दो मैचों की कप्तान थ्रेयस अय्यर संभालेंगे।

रणजी ट्रॉफी एलीट 2026-27 : कुल आठ मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त, 2 मैच में बारिश बनी ‘विलेन’

नई दिल्ली (एजेंसी)

रणजी ट्रॉफी एलीट 2026-27 में गुरुवार को 8 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए, जिनमें 2 मुकाबलों में बारिश ‘विलेन’ साबित हुई। आइए, ड्रॉ हुए उन सभी मुकाबलों के बारे में जानते हैं। ओडिशा बनाम सर्विसेज: भुवनेश्वर स्थित केआईआईटी स्टेडियम में खेले गए एलीट ग्रुप-सी के इस मैच में बारिश ‘विलेन’ साबित हुई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ओडिशा की टीम पहली पारी में महज 194 रन पर ढेर हो गई। इस पारी में पुल्कित नागर ने 47 रन देकर 6 विकेट चटकाए। इसके जवाब में सर्विसेज की टीम सिर्फ 12 ही

ओवर खेल सकी, जिसमें उसने बौएर कोई विकेट गंवाया, 40 रन बनाए। झारखंड बनाम दिल्ली: बारिश से प्रभावित यह मुकाबला रंची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला गया, जिसमें कप्तान आयुष बडोनी (नाबाद 210) और सुमित माथुर (नाबाद 150) की शानदार पारियों के दम पर दिल्ली ने अपनी पहली पारी 515/5 के स्कोर पर घोषित की। इसके जवाब में झारखंड की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 47 ओवर खेल सकी, जिसमें 4 विकेट गंवाकर 131 रन बनाए। चंडीगढ़ बनाम हिमाचल प्रदेश: एलीट ग्रुप-डी का ‘हार्ड-स्कोरिंग’ मैच चंडीगढ़ के सेक्टर-16



स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी चंडीगढ़ ने अपनी पारी 685/5 के स्कोर पर घोषित की। इस दौरान नेहल पजनी (222) और अर्जुन आजाद (147) ने दमदार पारियां खेलीं।

इसके जवाब में हिमाचल ने 177 ओवरों का सामना करते हुए 6 विकेट खोकर 559 रन बनाए। इस पारी में इनेश महाजन (121) और आकाश वशिष्ठ (नाबाद 126) ने शतक जड़े। उत्तराखंड बनाम

राजस्थान: देहरादून स्थित अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी में खेले गए एलीट ग्रुप-डी के इस मैच में राजस्थान की टीम पहली पारी में 272 रन पर ढेर हो गई। इस पारी में देवेंद्र बोरा ने सर्वाधिक 6 विकेट हासिल किए।

‘पेड़ो’ में अपने किरदार की चर्चा से खुश हैं जाह्नवी कपूर, बोलीं- ‘इसी तरह के रोल की तलाश थी’



फिल्म ‘पेड़ो’ में अभिनेत्री जाह्नवी कपूर के किरदार को दिखाए जाने के तरीके को लेकर काफी चर्चा हुई। हाल ही में वरुण धवन के साथ ‘कॉफी विद करण’ में शामिल होने के दौरान, उन्होंने इस स्पॉट्स ड्रामा में अपने किरदार को ‘ऑब्जेक्टिफाई’ किए जाने को लेकर हुई आलोचना पर खुलकर बात की। आलोचना को खारिज करने या चर्चा से बचने के बजाय, जाह्नवी ने इस मामले को एक अलग नजरिए से देखने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि उनके किरदार को लेकर हुई चर्चा से शायद अब उन अभिनेत्रियों के प्रति अधिक संवेदनशीलता आएगी, जो अपने चित्रण के कुछ पहलुओं को लेकर असहज महसूस करती हैं। जाह्नवी ने कहा, ‘मुझे खुशी है कि ‘पेड़ो’ में मेरे चित्रण को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना। शायद अगली बार जब कोई अभिनेत्री कहेगी कि वह असहज है, तो लोग उसे किसी एलियन की तरह नहीं देखेंगे। इस विषय पर बात करते हुए, जाह्नवी ने बताया कि वह इस मुद्दे पर बोलने में थोड़ी हिचकिचा रही थीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर कई लोगों ने कड़ी मेहनत की थी। ‘घड़क’ फेम अभिनेत्री ने कहा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ या कुछ कहना भी चाहिए या नहीं, लेकिन यह जरूरी था कि जो कुछ भी हुआ, उसमें अपनी जिम्मेदारी मैं खुद लूँ। मेरे मन पर इस बात का भारी बोझ था कि इस तरह की चीजों का हमारे समाज पर, खासकर महिलाओं पर, कितना नकारात्मक असर पड़ सकता है। जाह्नवी ने माना कि समाज पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर वह शर्मिंदगी महसूस कर रही थीं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि वह थोड़ी और सतर्क रह सकती थीं। उन्होंने कहा, ‘क्या मैं कुछ और कर सकती थी? क्या मैं और ज्यादा सतर्क रह सकती थी? क्या मैं इस पर कड़ा विरोध जता सकती थी? बिल्कुल, हां। क्या यह समस्याजनक था? क्या यह हद से ज्यादा ‘ऑब्जेक्टिफिकेशन’ था? क्या इसने एक तरह से यौन उत्पीड़न को भी बढ़ावा दिया? हां। अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने कई बार खुद से यह सवाल पूछा कि क्या उन्हें शूटिंग के दौरान और अधिक मजबूती से विरोध करना चाहिए था। (एजेंसी)

पहली बार पंकज त्रिपाठी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी अदिति राव हैदरी, ‘हेलेन’ का किरदार निभाएंगी

अभिनेत्री अदिति राव हैदरी आगामी पारिवारिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘पारिवारिक मनोरंजन’ में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के साथ नजर आएंगी। अभिनेत्री ने बताया कि को-स्टार पंकज त्रिपाठी के साथ काम करना उनके मजेदार अनुभवों में से एक रहा। अभिनेत्री का कहना है कि पंकज त्रिपाठी का सहज ह्यूमर सीन को हल्का और मजेदार बनाने में मदद करता है। अदिति राव हैदरी ने कहा, ‘पंकज जी के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करना सच में बहुत खुशी की बात थी। उनका ह्यूमर इतना सहज और नेचुरल है कि हर सीन हल्का और ज्यादा मजेदार लगने लगा।’ अभिनेत्री इस फिल्म में ‘हेलेन’ नाम का किरदार निभा रही हैं, जो एक प्रॉपर्टी मैनेजर और हाउसकीपर के रूप में रंजन के घर आती हैं। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री अदिति राव हैदरी ने कहा, यह एक ऐसी फिल्म है, जिसमें हमारे दर्शकों को रोमांस, ह्यूमर और फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा। यह एक ऐसी फिल्म है, जिसे हमारे दर्शक चाहने वालों के साथ देखना पसंद करेंगे। मुझे इस किरदार के साथ काम करने में बहुत मजा आया है। उसकी खूबियों को और वो अपने आसपास के लोगों से कैसे जुड़ती हैं, ये सब खोजने में। वहीं, पंकज त्रिपाठी ने फिल्म को

लेकर कहा, मुझे इस फिल्म में इसकी सादगी, किरदारों का असल जिंदगी से जुड़ा होना और ह्यूमर के छोट-छोटे पल बहुत पसंद आए, जो फैमिली स्टोरीज को खास बनाते हैं। इसमें परिवार की गर्मजोशी है, थोड़ा रोमांस है और वो मजा है जो इसे त्योहारों में देखने के लिए परफेक्ट बनाता है। इस फिल्म का हिस्सा बनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि दर्शक भी अपने चाहने वालों के साथ इस फिल्म को एन्जॉय करें। यह फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसमें रोमांस, ह्यूमर और फैमिली ड्रामा का तड़का है। फिल्म का मकसद त्योहारों के मौके पर दर्शकों को एक हल्की-फुल्की फिल्म देना है, जिसे वे अपने परिवार के साथ एन्जॉय कर सकें। वरुण वी शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले बृजेंद्र काला, अली अब्बास जफर और वरुण वी शर्मा ने लिखे हैं, जबकि डायलॉग बृजेंद्र काला ने लिखे हैं। इसे विनोद भानुशाली, कमलेश भानुशाली, हिमांशु किशन मेहता और एलिसिया जफर ने प्रोड्यूस किया है, वहीं अली अब्बास जफर क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं। ‘पारिवारिक मनोरंजन’ अदिति और पंकज की साथ में पहली फिल्म है, जो 13 नवंबर को सोनी लिव पर रिलीज होगी। (एजेंसी)



ऑस्कर की दौड़ में शामिल हुई प्रियंका चोपड़ा की शॉर्ट फिल्म ‘वी वर हियर’

जोनस की भारतीय शॉर्ट फिल्म ‘वी वर हियर’ को ऑस्कर की रेस में शामिल होने के लिए योग्य हो गई है। इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए प्रियंका ने कहा कि यह फिल्म एक समकालीन और महत्वपूर्ण विषय को नए तथ्य दिलचस्प अंदाज में प्रस्तुत करती है। प्रियंका चोपड़ा जोनस इस फिल्म से कार्यकारी निर्माता के रूप में जुड़ी हैं। शॉर्ट फिल्म ‘वी वर हियर’ एक मॉक्यूमेंट्री है, जो भारत के एक छोटे शहर में रहने वाले तीन ऐसे बुजुर्गों की कहानी दिखाती है, जो एआई के बढ़ते प्रभाव का विरोध करने के लिए धरेलू उपकरणों का रूप धारण कर लेते हैं। फिल्म को कई बड़े

शॉर्ट फिल्म फेस्टिवलों में अवॉर्ड मिल चुके हैं। पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल शॉर्टफेस्ट में ‘बेस्ट लाइव-एक्शन शॉर्ट फिल्म’ और ‘बेस्ट कॉमेडी शॉर्ट’ का पुरस्कार जीतने के बाद यह फिल्म ऑस्कर की दौड़ में शामिल होने के योग्य हो गई है। अभिनेत्री-प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा जोनस ने कहा, यह फिल्म एक ऐसे विषय पर मजेदार अंदाज में बात करती है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। मैं इस क्रिएटिव टीम को सपोर्ट करने के लिए एजीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर तुरंत तैयार हो गई, ताकि उनकी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फिल्म के राइटर-डायरेक्टर

प्रणव भसीन ने कहा, वी वर हियर’ एक छोटे और मजेदार आइडिया के तौर पर शुरू हुई थी। तीन अंकल जो एआई को रोकना चाहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे मुझे उनसे, उनकी दोस्ती और उनके जिद्दी होसले से प्यार हो गया। उन्होंने आगे कहा, भारत में हकीकत अक्सर कहानी से भी ज्यादा अजीब होती है और मॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट की वजह से मैं फिल्म को असली लोगों और असली जगहों से जोड़े रख पाया, साथ ही यह भी दिखा पाया कि चीजें कितनी बेतुकी हो सकती हैं। अब जब फिल्म ऑस्कर की रेस के लिए क्वालिफाई हो गई है, तो मैं अभी भी इसे

समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसे वैसे ही बनाया, जैसे मैं हर चीज बनाता हूँ। एक आइडिया, जो मुझे पागलपन भर लगा, उसका आखिर तक पीछा किया। मुझे कभी यकीन नहीं था कि मेरे दिमाग के बाहर भी किसी और की यह समझ आएगी। अपनी बात को खत्म करते हुए उन्होंने कहा, एक यांग फिल्ममेकर के तौर पर, मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है कि मेरे साथ एंड्रयू स्कॉट और प्रियंका चोपड़ा जोनस जैसे इतने अनुभवी और बेहतरीन लोगों का होना संभव हुआ। हम सभी इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उत्साहित हैं। (एजेंसी)



सृष्टि सिंह का तमिल डेब्यू, बोलीं- दर्शना सिर्फ मां नहीं, एक इंडिपेंडेंट महिला है

अभिनेत्री सृष्टि सिंह आगामी तमिल मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म ‘जॉन डे’ से तमिल सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म में अभिनेत्री दर्शना नाम की लड़की का किरदार निभा रही हैं। सृष्टि ने बताया कि दर्शना का किरदार उन्हें इतना पसंद आया कि वह खुद को इस फिल्म को करने से रोक नहीं पाई। अभिनेत्री ने कहा कि एक एक्टर के तौर पर वह खुद से अलग तरह का किरदार निभाना चाहती थीं और दर्शना का किरदार उनके लिए कुछ वैसा ही था। उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी और दर्शना को समझा, तो जाना कि वह असल जिंदगी में मुझसे बिल्कुल अलग है और यही बात मुझे सबसे पहले इस रोल की तरफ खींच लाई। एक एक्टर के तौर पर आप अलग-अलग किरदार निभाना चाहते हैं, खासकर ऐसे किरदार जो आपकी अपनी जिंदगी और हकीकत से बिल्कुल अलग हों। उन्होंने आगे कहा, ‘यह किरदार मुझे इतना पसंद आया कि इसे निभाने की मेरी उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि, मेरे साथ पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। मुझे पता था कि दर्शना को समझने, उसके अनुभवों को अपनाने और इस किरदार को अपना बनाने के लिए मुझे एक पूरी प्रोसेस से गुजरना होगा, जो मेरे लिए काफी एक्ससाइटिंग रही। अभिनेत्री सृष्टि सिंह ने अपने किरदार के बारे में बताते हुए कहा, हमारी इंडस्ट्री में कई बार एक्टरों को उनके किरदारों के हिसाब से एक ही तरह के रोल में डाल दिया जाता है, लेकिन दर्शना एक ऐसी मां है, जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खेला है और अपने परिवार, पति और बच्चों से जुड़ी कई चुनौतियों से जूझ रही है। उसकी अपनी परेशानियां और अपने तजुबे हैं। (एजेंसी)

भारत, बेल्जियम और लक्जमबर्ग एयरोस्पेस, रिसर्च और इनोवेशन में बढ़ाएंगे सहयोग

नई दिल्ली (एजेंसी)

भारत, बेल्जियम और लक्जमबर्ग आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एयरोस्पेस, अनुसंधान, नवाचार और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने पर सहमत हुए हैं। यह जानकारी वाणिज्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में दी गई। मंत्रालय के अनुसार, भारत-बेल्जियम-लक्जमबर्ग आर्थिक संघ (बीएलईयू) के संयुक्त आर्थिक आयोग (जेईसी) का 19वां सत्र लक्जमबर्ग में आयोजित किया गया। इस बैठक में भारत, बेल्जियम और लक्जमबर्ग के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समूहों की समीक्षा करने और प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की गई। जेईसी की सह-अध्यक्षता वाणिज्य सचिव राजेश



अग्रवाल, बेल्जियम के संघीय विदेश मामलों, विदेश व्यापार एवं विकास सहयोग मंत्रालय में भू-अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक कटनीति के महानिदेशक फिलिप वेंडेन बुल्के और लक्जमबर्ग के विदेश एवं यूरोपीय मामलों, रक्षा, विकास सहयोग एवं विदेश व्यापार मंत्रालय के महासचिव हेनरी शुमाकर ने की। बैठक में कई प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा हुई। इनमें लॉजिस्टिक्स, विशेष रूप से हवाई संपर्क और बंदरगाह, नवीकरणीय ऊर्जा एवं

स्वच्छ प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं और फिनटेक, डिजिटल बदलाव एवं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), स्वास्थ्य सेवा एवं जीवन विज्ञान, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्कारी उद्योग शामिल हैं। बैठक में एयरोस्पेस, अनुसंधान एवं नवाचार, उच्च शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करने और कारोबार भागीदारी एवं निवेश साझेदारी बढ़ाने के रास्ते तलाशने का अवसर मिला।

करने, बाजार तक पहुंच आसान बनाने और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के अवसरों की पहचान करने के उद्देश्य से बाजार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जेईसी की बैठक में तीनों देशों को अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान-प्रदान करने, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करने और कारोबार भागीदारी एवं निवेश साझेदारी बढ़ाने के रास्ते तलाशने का अवसर मिला।

भारत को वित्त वर्ष 35 तक करीब 1.5 अरब स्व्वायर फीट प्राइवेट एजुकेशन इन्फ्रा की होगी आवश्यकता : रिपोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)

भारत को वित्त वर्ष 35 तक करीब 1.5 अरब स्व्वायर फीट अतिरिक्त प्राइवेट एजुकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। इससे देश में रियल एस्टेट डेवलपर्स और संस्थागत निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। यह जानकारी शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में दी गई। सीबीआईआई साउथ एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह मांग भारत की बढ़ती युवा आबादी, स्कूलों/कॉलेजों में दाखिले की बढ़ती संख्या, निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बढ़ती मांग के कारण पैदा हो रही है। इसमें से लगभग 0.9 बिलियन वर्ग फुट की अतिरिक्त मांग निजी के-12 स्कूलों से आएगी, जबकि निजी (बिना सरकारी सहायता वाले) उच्च शिक्षण संस्थानों की हिस्सेदारी लगभग 0.4 बिलियन वर्ग फुट होगी। रिपोर्ट में

यह भी बताया गया है कि संस्थागत निवेशक, विशेष रूप से समृद्ध शहरी बाजारों में, बड़े स्तर पर विस्तार करने वाले प्रीमियम के-12 प्लेटफॉर्मस में रुचि दिखा रहे हैं। बयान में कहा गया, निवेशक ‘स्ट्रक्चर्ड ऑपेरिंग’ कंपनी-प्रॉपर्टी कंपनी’ मॉडल पर भी विचार कर रहे हैं, जो रियल एस्टेट के स्वामित्व को शैक्षणिक कार्यों से अलग करता है। सीबीआईआई में भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के चेयरमैन और सीईओ अंशुमन मैजजीन ने कहा, जैसे-जैसे निजी शिक्षा प्रदाता अलग-अलग बाजारों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं, वैसे-वैसे स्केलेबल बुनियादी ढांचा और ऑपेरिंग मॉडल लंबी अवधि की वृद्धि में मददगार साबित हो सकते हैं। इस मांग को पूरा करने में डेवलपर्स और स्थापित शिक्षा संचालकों के बीच की साझेदारी एक अहम भूमिका निभा सकती है।

भारत को 500 गीगावाट के वलीन एनर्जी लक्ष्य को पाने टेक्नोलॉजी पर करना होगा फोकस : इंडस्ट्री

नई दिल्ली (एजेंसी)

भारत को अपने 500 गीगावाट की वलीन एनर्जी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जलवायु निवेश, अनुकूलन वित्त (अडैप्टेशन फाइनेंस), टेक्नोलॉजी सहयोग और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह जानकारी तुर्किए में होने वाली कॉप31 क्लाइमेट समिट से पहले इंडस्ट्री चैम्बर्स की ओर से दी गई। इंडस्ट्री चैम्बर्स एसोसिएम ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की बढ़ोतरी के साथ, जुलाई 2026 तक भारत की गैर-जीवाश्म



ईंधन आधारित बिजली क्षमता 300.5 गीगावाट तक पहुंच गई है। बयान के अनुसार, भारत ने 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले ही अपनी कुल बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 54% से अधिक कर ली है। एसोसिएम के अध्यक्ष निर्मल के. मिंछ ने कहा, ‘देश ने यह साबित कर दिया है कि एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

स्वच्छ ऊर्जा को बढ़े पैमाने पर अपना सकती है। भारत ने तय समय से पांच साल पहले ही अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का आधे से अधिक हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि कॉप31 में अमल पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें उद्योग जगत की मुख्य भूमिका हो। मिंछ ने कहा कि भारत के 2030 के जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। साथ ही, बैटरी स्टोरेज की मांग 2027 तक 37 गीगावाट घंटा से बढ़कर 2031-32 तक 236 गीगावाट घंटा तक पहुंचने का अनुमान है।

सोना-चांदी खरीदने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी सही तौल,नए नियम लागू

जयपुर (एजेंसी)

सोना-चांदी खरीदने वाले उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और तौल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। उपभोक्ता मामले विभाग ने राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम 29 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी हो गए हैं। नए प्रावधानों के तहत सोना, चांदी एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद-बिक्री में निर्धारित मानकों वाले सटीक कांटों का उपयोग अनिवार्य किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार, बहुमूल्य धातुओं की तौल के लिए Class I (विशेष



सटीकता) अथवा Class II (उच्च सटीकता) श्रेणी के कांटों का ही उपयोग किया जा सकेगा। इन कांटों का सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम होना आवश्यक है। इससे कम मात्रा में भी तौल की सटीकता

सुनिश्चित होगी तथा उपभोक्ताओं को खरीदी गई सोना-चांदी की सही मात्रा मिल सकेगी। **स्वर्णकारों एवं सर्राफा व्यापारियों को करना होगा नियमों का पालन**- उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी स्वर्णकारों, सर्राफा व्यापारियों

एवं बहुमूल्य धातुओं का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों से नए प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने की अपील की है। व्यापारियों को सोना, चांदी एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं की तौल के लिए निर्धारित Class I अथवा Class II श्रेणी के कांटों का उपयोग करना होगा। साथ ही, कांटों का सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम होना चाहिए। विभाग ने व्यापार में प्रयुक्त कांटों का नियमानुसार सत्यापन करवाने तथा उनका वैध सत्यापन प्रमाण-पत्र रखने के निर्देश दिए हैं। जिन व्यापारियों के पास वर्तमान में निर्धारित मानकों के अनुरूप काटे उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें नियमों के अनुरूप कांटों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और पारदर्शिता सर्वोपरि- उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य दिवाली सहित पूरे वर्ष सोना-चांदी की खरीद-बिक्री में सही तौल एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के हितों की प्रभावी रक्षा करना है। नए प्रावधानों से बहुमूल्य धातुओं के कारोबार में तौल संबंधी अनियमितताओं की आशंका कम होगी तथा उपभोक्ताओं को उनके भुगतान के अनुरूप धातु की सही मात्रा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि दिवाली पर सोना-चांदी खरीदते समय तौल पर विशेष ध्यान दें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर शिकायत दर्ज कराएं।